[श्री जैनुल बशर]

उक्त बांध के बनाए जाने की कार्यवाही अदूरदर्शितापूर्ण है और इस से गाजीपुर और बलिया जिलों में बड़े पैमाने पर रोष व्याप्त है। इस बात को रोके जाने के लिए उस क्षेत्र की जनता द्वारा सत्याग्रह की भी धमकी दी गई है।

केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि उक्त बांध बनाए जाने की कार्यवाही को तुरन्त रद्द करे जिस से कि उस क्षेत्र के लोग राहत की सांस लें।

(vi) INSTALLATIONS OF A RADIO STATION IN THE BORDER DISTRICTS OF BARMER/JAISELMER OF RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन लोकमहत्व के निम्नलिखित प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

केन्द्र सरकार ने रेडियो प्रसारण की दृष्टि से राजस्थान प्रांत के सीमावर्ती एवं पिछड़े लोक सभा क्षेत्र बाड़मेर एवं जसलमेर जिसका क्षेत्रफल 70 हजार वर्ग किलोमीटर है और जो केरल प्रान्त से दुगुना और हरियाणा प्रान्त से पौने दो गुणा है, की घोर उपेक्षा कर रखी है।

आल इंडिया रेडियो के दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सूरतगढ़ स्टेशनों की आवाज उक्त क्षेत्र के आधे हिस्से में बिल्कुल मंद पहुंचती है और आधा क्षेत्र रेडियो प्रसारण की सेवाओं से वंचित रहता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बाड़मेर एवं जैसलमेर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव था, परन्तु वित्तीय कठिनाई का सहारा लेकर उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित नहीं किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में भी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है और उक्त क्षेत्र की घोर उपेक्षा की जा रही है। उक्त क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा पर आया हुआ है। उक्त क्षेत्र देश का प्रहरी है, परन्तु उक्त क्षेत्र की जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए रेडियो प्रसारण की सेवाओं का लाभ भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है।

दूसरी ओर पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन करांची, लाहोर आदि बड़ी शक्ति के स्टेशन हैं, जिनकी बुलन्द आवाज मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर एवं जैसलमेर के सारे हिस्से में पहुंचती है। सूचना और प्रसारण विभाग इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है। मेरा सूचना एवं प्रसारण मंत्री से निवेदन है कि वे बाड़मेर एवं जैसलमेर में सन् 1981-82 में रेडियो स्टेशन स्थापित करा-कर जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करें।

(vii) ATROCITIES ON PRISONERS IN CENTRAL JAIL, SAMASTIPUR AND OTHER PARTS OF THE COUNTRY.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय मैं नियम 777 क अधीन लोक महत्व के निम्नलिखित प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

देश के अनेक भागों से जेल में हो रहे कैदियों पर अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी भागलपुर कांड की गूंज दब भी नहीं पायी थी कि बिहार पुलिस ने समस्तीपुर केन्द्रीय जेल में 14 जनवरी, 1981 को निर्दोष कैदियों पर निर्ममतापूर्ण गोली चलाकर

दर्जनों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिन में एक छात्र नेता भी सम्मिलित है । सवा सौ से अधिक कैदी गोली से घायल हुए। अधिकांश कैदियों को (कमरे) बैरक से खींच कर मारा गया । कुछ कैदी अस्पताल में चिकित्सा के अभाव में मर गए। कैदियों की मुख्य मांगें थीं कि उन्हें नियमानुसार कम्बल दिया जाए, जेल धांधली को समाप्त किया जाए, जेल मेनुअल के अनुसार खाना, कपड़ा आदि दिया जाए तथा कैदियों से मिलने वालों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए ।

जेल की आम शिकायत है कि कैदियों को घटिया किस्म का खाना दिया जाता है तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार जेल संहिता में सुधार करे, दोषी पदाधिकारियों को दंडित करे, प्रत्येक मृतक परिवार को एक लाख रुपया मुआवजे के रूप में दे तथा घायलों को पचास हजार रुपया दे।

(viii) SHORTAGE OF EDIBLE OIL IN DELHI.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central): Under Rule 377, I am making a statement:

Besides non-availability of sugar and wheat in 80 per cent of the ration shops in Delhi edible oil has also now disappeared.

Though STC has large supplies of edible oils and has delivered full supply of oil for the month of February meant for public distribution many ration shops in Bombay, Delhi and number of places have stopped supplies of palm oil to the consumers. The reason behind the non-availability of edible oil is not because there is shortage of imported oil but because of its open market sale as groundnut oil at higher prices. The price of the imported oil is fixed at Rs. 8.25 for retailers whereas the price of the imported oil is fixed at Rs. 8.25 for with the imported oil, is Rs. 15 to Rs. 18 a K.G. My personal experience is that I have bought groundnut oil from a Delhi shop which smells like rapeseed oil.

I request the Minister of Civil Supplies to institute an inquiry into the matter and save the consumer from buying adulterated oil at exhorbitant price.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह तेल खरीदा है, जो मैं लाई हूं, जो कि मैं आपके सामने नहीं रखती हूं लेकिन उसको टेस्ट होकर जांच करवानी चाहिए । क्योंकि इस प्रकार का तेल यहां दिल्ली की मार्केट में मिल रहा है ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): आप पकौड़ी बनवाकर सबको खिलवाइए ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : तो इस आयल का बनवा लूं ।

(ix) DESERTION OF ASIAN GAMES COACHING CAMP BY INDIAN FOOTBALL PLAYERS

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): Mr. Chairman, Sir, 17th February, 1981 will be termed as black day for the Indian sportsmen in the world sports history because of the anti-national act of nineteen football players who deserted from the Asian Games Coaching Camp by signing a written undertaking giving the preference to Club's and individual interest to nation's interest. It will not